6.00 P.M.

with their plans on consolidation and merger of public sector banks. it was reported that the SBI management will expedite the merger of the associate banks like SBT with SBI. It is astonishing that such thing again emanates at a time when the so-called Global Banks in the UK and the USA have tumbled as part of global banking, financial and economic crisis. Sir, 75 per cent of the bank deposits in India are household deposits. This must be utilised for the welfare of the masses for the development of agriculture, small-scale industries, etc. The merger would lead to closure of rural branches in the name of competitiveness. The proposal of merger of State Bank of Travancore with SBI will not be in the interest of the nation, national economy, and banking system. The proposed merger would obviously result in closure of the large number of branches of SBT and result in losing the jobs and job security of employees and officers. This also curtails the banking services for the people. So, I urge the Central Government to intervene to withdraw the decision of merger and ensure the identity of SBT.

Demand to provide employment under NREGA to the people affected by famine

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (राजस्थान) : महोदय, देश में और विशेषकर उत्तर-पश्चिम भाग में मानूसन आने में लगभग दो सप्ताह की देरी हो गई है। राजस्थान में मानसून की पहली बरसात जुलाई के पहले सप्ताह में आई। कुछ जिलों में मासिक औसत के बराबर वर्षा हो गई, किन्तु गरमी के कारण वर्षा के उपरांत भी अभी बुआई शुरू नहीं हुई। राजस्थान जैसी स्थिति पंजाब, हरियाणा, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और अन्यत्र भी दिखाई देती है। इससे न केवल भूमिहीन, लघु एवं सीमांत कृषक और कृषि मजदूर ही प्रभावित हुए हैं, अपितु वे काश्तकार भी प्रभावित हो गए हैं, जो उपरोक्त श्रेणियों में नहीं आते। इनको अपने निर्वाह के लिए तत्काल आजीविका की आवश्यकता है। राज्य सरकार आपदा प्रबंधन के अन्तर्गत इनके लिए व्यवस्था नहीं कर सकती और योजना कार्यों पर ऐसे सभी लोगों को रोज़गार नहीं दिया जा सकता। इसका एकमात्र विकल्प इनको नरेगा के अंतर्गत कार्य चलाकर रोज़गार दिलवाने का है। इसके लिए नरेगा के बी.पी.एल. होने के मानदण्ड में अस्थाई रूप से छूट देनी होगी, साथ ही जितने दिन ऐसी स्थिति रहे उस अवधि को नरेगा की 100 दिन की समय सीमा से बाहर रखना होगा।

महोदय, समस्या केवल राजस्थान या किसी जिले अथवा तहसील विशेष की नहीं है। देश के बहुत सारे हिस्से इससे प्रभावित हैं। अतः मैं मांग करता हूं कि नरेगा के मानदण्डों में छूट देते हुए सूखा प्रभावित क्षेत्र के किसानों को नरेगा के अन्तर्गत रोजगार दिलवाने की तत्काल व्यवस्था की जाए और बी.पी.एल. के मानदण्डों और 100 दिन की अवधि में शिथलन करते हुए समस्या का समाधान किया जाए। धन्यवाद।

Need to review the regulations notified by CERC to fulfil the objective of 'Electricity for All' under the Bharat Nirman Programme

SHRI SILVIUS CONDPAN (Assam): Sir, the regulations 2009-14 of CERC contain several enabling provisions to hike tariff of Central Sector Utilities, which are not conducive towards the common electricity consumers. The regulations notified by the CERC need to be reviewed otherwise, the objective of “Electricity for all” under the Bharat Nirman Programme will be defeated. NER is considered as most backward region of India with a per capita consumption of electricity of 111 KWh against national average of 411 KWh, and only 24 per cent village household accessed electricity in